

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रक्ष प्रक्ष संख्या 5353
उत्तर देने की तारीख: 03.04.2025

वन धन केंद्र

5353. श्री मुरारी लाल मीना:

श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार, विशेषकर दौसा जिले सहित राजस्थान में कुल कितने वन धन केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधि का व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जनजातीय समुदायों की आजीविका और आर्थिक स्थितियों पर वन धन केन्द्रों की स्थापना के प्रभाव का कोई आकलन किया है, विशेषकर उन राज्यों में जहां शहद, औषधीय पौधे और अन्य वन आधारित उत्पाद आय के प्रमुख स्रोत हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान के दौसा जिले में वन धन केन्द्रों के माध्यम से कोई विशेष पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है, और

(ड) क्या राजस्थान के जनजातीय समुदायों, विशेषकर दौसा के जनजातीय क्षेत्रों को कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गदास उड्के)

(क) से (ड) मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) नामक योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिनके अंतर्गत आजीविका के अवसर प्रदान करने और जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सहित राज्य सरकारों को वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। आज की तिथि तक, पीएमजेवीएम के तहत 11.83 लाख लाभार्थियों को जोड़ने वाले 3959 वीडीवीके और पीएम-जनमन के तहत 0.43 लाख लाभार्थियों को जोड़ने वाले 506 वीडीवीके स्वीकृत किए गए हैं। इन वीडीवीके ने आज की तिथि तक लगभग 109 करोड़ रुपये की बिक्री की है। राजस्थान सहित राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <https://trifed.tribal.gov.in/sites/default/files/2025-03>Status%20of%20VDVKs%20as%20on%2028.02.2025.pdf>

राजस्थान राज्य सरकार से दौसा जिले में वीडीवीके की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।
